

संदर्भ Ref.: नि.से.वि.ISD/241/2026-27

दिनांक Date : 29.10.2026

बीएसई लिमिटेड BSE Ltd.
बीएसई लिस्टिंग सेंटर BSE Listing Centre
स्क्रिप कोड Scrip Code - 532 477

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड
National Stock Exchange of India Ltd.
निप्स / NEAPS
स्क्रिप कोड Scrip Symbol-UNIONBANK-EQ
सिक््योरिटी Security - UBI-AT/BB

महोदया Madam/महोदय Sir,

Subject : Notice Published in the Newspaper - Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

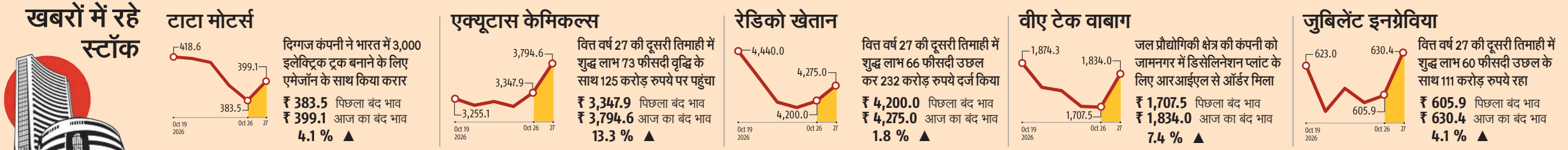
We enclose copies of the Newspaper publication of Special Window for Relodgement of Transfer Requests of Physical Shares published in the Newspaper - Business Standard English & Hindi edition and Marathi Newspaper - Navshakti on 28th October 2026. This is for your information and appropriate dissemination

भवदीय Yours faithfully,

ASHISH
MISHRA
Digitally signed by
ASHISH MISHRA
Date: 2026.10.29
12:11:43 +05'30'

(Ashish Mishra)
Company Secretary

Encl. - As above.



संक्षेप में

रेडिको खेतान का लाभ

232 करोड़ रुपये पर

शराब बनाने वाली कंपनी रेडिको खेतान का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में 66.5 प्रतिशत बढ़कर 232.34 करोड़ रुपये रहा। कंपनी के अनुसार, पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की जुलाई-सितंबर तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 139.55 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की सितंबर तिमाही में उसकी परिचालन आय सालाना आधार पर 10.4 प्रतिशत बढ़कर 5,582.71 करोड़ रुपये हो गई। इस दौरान कुल बिक्री मात्रा 10.1 प्रतिशत बढ़कर 98.3 लाख पेटी रही।

मोरेपेन लैबोरेटरीज

को हुआ मुनाफा

मोरेपेन लैबोरेटरीज लिमिटेड ने मंगलवार को बताया कि सितंबर में समाप्त चालू वित्तवर्ष की दूसरी तिमाही में उसका शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर बढ़कर 88.89 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में 41.04 करोड़ रुपये का शुद् मुनाफा अर्जित किया था। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसका राजस्व बढ़कर 746.5 करोड़ रुपये हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 411.57 करोड़ रुपये था। इस दौरान कंपनी का कुल खर्च भी बढ़कर 638.64 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्तवर्ष की समान तिमाही में यह 396.34 करोड़ रुपये था।

वर्ल्ड होटल्स के तहत लाए गए 4,000 होटल

अमेरिका स्थित हॉस्पिटैलिटी समूह बीडब्ल्यूएच होटल्स ने बुधवार को 100 देशों में अपने 4,000 से अधिक होटलों को वर्ल्ड होटल्स के तहत नए वैश्विक मास्टर ब्रांड के रूप में लाने का ऐलान किया। इस बदलाव से 18 ब्रांड, लॉन्गवूटी कार्यक्रम और डिजिटल प्लेटफॉर्म एक जगह आ जाएंगे, जबकि स्वतंत्र होटलों को अपने मौजूदा नामों और ब्रांड पहचान को बनाए रखने की अनुमति होगी। इस बारे में वर्ल्ड होटल्स के अध्यक्ष और सीईओ लैरी कुकुलिक ने कहा, ‘हमारे पास व्यवहारिक रूप से हर प्रकार की यात्रा के लिए एक होटल है, लेकिन कई यात्री हमारे पोर्टफोलियो के केवल एक हिस्से को ही जानते हैं।’ यह हॉस्पिटैलिटी समूह वर्तमान में देश में 34 होटल संचालित करता है और 26 होटल निर्माणाधीन हैं।

जियो ने जोड़े 27.13 लाख मोबाइल ग्राहक

रिलायंस जियो ने सितंबर महीने में 27.13 लाख मोबाइल ग्राहक जोड़े। यह भारती एयरटेल के 26.92 लाख नए ग्राहकों से अधिक है। दूरसंचार नियामक ट्राई के मंगलवार को जारी आंकड़ों से यह जानकारी मिली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के मासिक आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में वोडाफोन आइडिया ने 5.50 लाख और सार्वजनिक क्षेत्र की भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने 6.26 लाख मोबाइल ग्राहक जोड़े। सितंबर के अंत में जियो के मोबाइल ग्राहकों की संख्या बढ़कर 51.11 करोड़ हो गई, जबकि एयरटेल के ग्राहक 49.43 करोड़ रहे। वोडाफोन आइडिया के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 20 करोड़ से अधिक और बीएसएनएल की 9.43 करोड़ रही।

भाषा

‘विनिर्माण में निर्यात हब बनेगा भारत’

वैबटेक ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए रेलवे के साथ किया करार

शाइन जेकब चेन्नई, 27 अक्टूबर

वैबटेक कॉर्पोरेशन भारत को वैश्विक विनिर्माण और इंजीनियरिंग हब के रूप में मजबूत कर रही है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि उसने प्रतिष्ठित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कार्यक्रम की मदद के लिए कई ट्रांजिट सेवाओं के लिए भारतीय रेलवे से ऑर्डर किए हैं। लगभग 9.4 करोड़ डॉलर (लगभग 839 करोड़ रुपये) के इन समझौतों से भारतीय रेलवे को सेवा विस्तार, रखरखाव और यात्री सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। वैबटेक ट्रांजिट के प्रेसिडेंट पास्कल श्वेत्ज़र ने मंगलवार को बिज़नेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा कि कंपनी अपने देश के ग्राहकों को सेवाएं देने के साथ-साथ यूरोप और अमेरिका सहित अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी विस्तार की योजना बना रही है। श्वेत्ज़र ने कहा कि कंपनी यूरोप, अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में निर्यात के लिए भारत को विनिर्माण और इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता वाला वैश्विक केंद्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी रणनीति

मारुति सुजूकी का मुनाफा गिरा

लागत वृद्धि, मुद्रा विनिमय के प्रतिकूल प्रभाव और म्युचुअल फंड में नुकसान की पड़ी छाया

दीपक पटेल नई दिल्ली, 27 अक्टूबर

मारुति सुजुकी इंडिया का एकीकृत शुद्ध मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में 26.4 फीसदी घटकर 2,466.1 करोड़ रुपये रहा। कच्चे माल की लागत बढ़ने, मुद्रा विनिमय के प्रतिकूल असर और म्युचुअल फंड निवेश में नुकसान से कंपनी का मुनाफा प्रभावित हुआ है।

मारुति सुजुकी के प्रबंध निदेशक और सीईओ हिसाशी ताकेउची ने वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘वित्त वर्ष 2027 में अब तक हम तीन बार कीमतें बढ़ा चुके हैं। साथ ही हम सभी खर्चों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप पहली तिमाही से तुलना करें तो दूसरी तिमाही में कुछ सुधार होता दिखेगा। अगले छह महीनों में हम सही समय देखकर कीमतें बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इससे हमारे मुनाफे की स्थिति और बेहतर होगी।’ वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कंपनी की आय पिछले साल की समान तिमाही की तुलना में 26 फीसदी बढ़कर लगभग 53,355 करोड़ रुपये रही। इस दौरान कुल खर्च कहीं 29.7 फीसदी बढ़कर करीब 50,619 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। इसका मतलब यह हुआ कि खर्चों में हुई बढ़ोतरी आय में हुई वृद्धि से अधिक रही, जिससे अधिक बिक्री के बावजूद मुनाफे पर दबाव पड़ा।

छोटी कारों के बारे में मारुति सुजुकी के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा कि 2047 में भी जब भारत के विकसित हो जाएगा, तब भी देश में छोटी कारों का देशों में शामिल होने की उम्मीद है, तब भी यहीं छोटी कारों का एक बड़ा बाजार बना रहेगा क्योंकि आबादी के एक बड़े हिस्से को किफायती परिवहन की

जरूरत बनी रहेगी। भार्गव ने कहा, ‘मेरा मानना है कि 2047 में जब भारत के चेयरमैन आर सी भार्गव ने कहा कि 2047 में भी जब भारत के विकसित हो जाएगा, तब भी देश में छोटी कारों का एक बड़ा बाजार बना रहेगा क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है।’ उन्होंने कहा कि भारत का कार बाजार विविधतापूर्ण बना रहेगा, जहां अलग-अलग आय वर्गों के खरीदार विभिन्न कीमतों की गाड़ियां खरीदना चाहेंगे।

टाटा मोटर्स का रणनीतिक कदम

इवेको के अधिग्रहण का रास्ता हुआ साफ

शी। लेकिन बीते 15 महीनों में इस सौदे को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कंपनी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा।

बीते 16 अक्टूबर को एक असाधारण आम बैठक में लगभग 53 फीसदी सदस्यों ने कथित तौर पर सौदे के पक्ष और 12 फीसदी ने विरोध में मतदान किया। कुल 35 फीसदी सदस्य ऐसे रहे, जिन्होंने मतदान नहीं किया। बैठक में शेयरधारकों ने बोर्ड की ओर से रखे गए सभी प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिनमें शेयर सौंपने की न्यूनतम स्वीकृति सीमा को 95 फीसदी से घटाकर 80 फीसदी करना भी शामिल है। इवेको ने शेयर बाजार फाइलिंग में कहा, ‘इवेको के सामान्य शेयरों के लिए टाटा मोटर्स द्वारा लॉन्च किए गए सार्वजनिक टेंडर प्रस्ताव (ओपीए) के हिस्से के रूप में स्वीकृति की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर को 97,078,765 आवेदन जमा किए गए।

माइक्रोसॉफ्ट देगी

कर्मियों को मानक सेवरेंस पैकेज

माइक्रोसॉफ्ट अपने स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति कार्यक्रम के तहत भारत में कर्मचारियों को मानक सेवरेंस पैकेज देगी। इसमें पूरे कार्यकाल के दौरान हर वर्ष के लिए एक महीने का मूल वेतन, स्वास्थ्य बीमा और करियर बदलाव में मदद आदि शामिल हैं। कंपनी ने कहा कि कर्मचारियों को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए 1 दिसंबर तक नियमित लेना होगा। कंपनी ने सोमवार को वैश्विक स्तर पर लगभग 60,000 लोगों को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश की है, जो उसके कुल 2,23,000 कर्मचारियों का 25 फीसदी है। कंपनी में एक चौथाई कार्यबल को स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति की पेशकश का निर्णय ऐसेमन्यों में आया है जब दुनिया भर की कंपनियां एआई के साथ दक्षता में सुधार और राजस्व बढ़ाने के तरीके तलाश रही हैं।

बीएस

कोल इंडिया का पूंजीगत व्यय 27 फीसदी बढ़ा

सुधीर पाल सिंह नई दिल्ली, 27 अक्टूबर

सार्वजनिक क्षेत्र की खनन कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) का चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही (अप्रैल से सितंबर) के दौरान पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 6,283 करोड़ रुपये के मुकाबले 27 फीसदी बढ़कर 7,996 करोड़ रुपये हो गया है।

कंपनी ने मंगलवार एक बयान में कहा, ‘यह व्यय 7,286 करोड़ रुपये के पहली छमाही लक्ष्य से अधिक रहा, जो इस अवधि के लिए नियोजित व्यय का 109 फीसदी और 16,500 करोड़ रुपये के वार्षिक कैपेक्स लक्ष्य का 48 फीसदी से अधिक है।’

वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में सीआईएल को सबसे बड़ा 2,152 करोड़ रुपये का

कंपनी समाचार 13

एलएंटैडटी के लाभ में 33 फीसदी वृद्धि

सुधीर पाल सिंह नई दिल्ली, 27 अक्टूबर

विनिर्माण क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एलएंटैडटी ने मंगलवार को सितंबर तिमाही के लिए 33 फीसदी की छलांग के साथ 5,202 करोड़ रुपये का समेकित लाभ (पीएटी) दर्ज किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 3,926 करोड़ रुपये था। परियोजना, उत्पाद और विनिर्माण पोर्टफोलियो में निरंतर प्रगति से तिमाही के तीन महीनों के दौरान कंपनी का समेकित राजस्व भी 16 फीसदी बढ़कर 78,750 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी ने 28 फीसदी की वृद्धि के साथ 1,47,665 करोड़ रुपये के ऑर्डर हासिल किए हैं। ये हाइड्रोकार्बन, कार्बनलाइट सॉल्यूशंस, पब्लिक स्पेसेस और एयरपोर्ट और पावर ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन व्यवसायों से जुड़े बड़े ठेके हैं। कंपनी ने कहा कि सितंबर 2026 के अंत में समूह स्तर पर उसका समेकित ऑर्डर बुक 8,53,514 करोड़ रुपये रहा, जो मार्च 2026 की तुलना में 15 फीसदी की वृद्धि दर्शाता है। अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर कुल ऑर्डर बुक का 54 फीसदी रहे। कंपनी के चेयरमैन और एमडी एसएन सुब्रमण्यन ने कहा, ‘कंपनी ने लगातार बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में भी शानदार प्रदर्शन किया है। यह ग्राहकों के विश्वास और भौगोलिक क्षेत्रों में बड़े एवं जटिल ऑर्डर हासिल करने की हमारी क्षमता को दर्शाता है।



ढाका मेट्रो के निर्माण का ठेका मिला

बुनियादी ढांचा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी लार्सन एंड टुब्रो (एलएंटैडटी) को बांग्लादेश की ढाका मेट्रो रेल परियोजना (लाइन-1) के लिए दो अहम पैकेजों के डिजाइन और निर्माण का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी के परिवहन कारोबार वर्टिकल को मिले इन ऑर्डर में ट्रेक निर्माण, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, सिग्नलिंग, टेली कम्युनिकेशन और प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर से जुड़े काम शामिल हैं। यह बांग्लादेश की पहली भूमिगत मेट्रो रेल परियोजना है। इससे पहले एलएंटैडटी ने ढाका मेट्रो की लाइन 6 के लिए एकीकृत रेलवे तंत्र का काम हासिल किया था और उसे सफलतापूर्वक पूरा किया था। यह बांग्लादेश का पहला मेट्रो रेल कॉरिडोर है जो फिलहाल व्यावसायिक रूप से संचालित हो रहा है।

जेएलएल ने गिफ्ट सिटी में ग्लोबल ट्रेजरी सेंटर खोला

वैश्विक रियल एस्टेट सेवा फर्म जेएलएल ने अपने वैश्विक कारोबार के ट्रेजरी परिचालन को एक जगह करने और पूंजी नियोजन में सुधार के लिए गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में कॉर्पोरेट ट्रेजरी सेंटर स्थापित किया है।

कंपनी ने गिफ्ट सिटी के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) में जोन्स लैंग लालसेल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (जेएलएल इंडिया) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जेएलएल फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की है। जेएलएल इंडिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी राधा धीर ने कहा, ‘गिफ्ट सिटी का मॉडल नियामक मजबूती और बेहतरीन प्रतिभाओं का सही मिश्रण है।’

यूनियन बैंक
ऑफ इंडिया


Union Bank
of India

अच्छे लोग, अच्छा बैंक

Good people to bank with

केंद्रीय कार्यालय, निवेशक सेवाएं, यूनियन बैंक भवन, 239, विधान भवन मार्ग, 12वां तल, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021, दूरभाष: 022-22896636

ईमेल: investorservices@unionbankofindia.bank.in

वेबसाइट: <https://unionbankofindia.bank.in>

शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

भौतिक शेयरों के अंतरण अनुरोधों को पुनः प्रस्तुत करने हेतु विशेष अवसर

सेबी परिपत्र सं. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/1/3750/2026 दिनांक 30 नवम्बर 2026 के अनुगलन में, शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि भौतिक शेयर प्रमाण-पत्रों के अंतरण संबंधी अनुरोधों के पुनः प्रस्तुतिकरण के लिए दिनांक **5 फरवरी, 2026 से 4 फरवरी, 2027** तक एक (1) वर्ष की अवधि हेतु एक विशेष अवसर प्रदान किया गया है।

यह सुविधा उन अंतरण वितेलों पर लागू होगी, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2019 से पूर्व प्रस्तुत किए गए थे, किंतु दस्तावेजों, प्रक्रिया अथवा अन्य कारणों से अस्वीकृत कर दिए गए थे, वापस लौटा दिए गए थे अथवा जिन पर कार्रवाई नहीं की जा सकी थी।

जो शेयरधारक पहले की समय सीमा से नुक़ गए थे, वे अब नीचे दिए गए पते पर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

पता: यूनित: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया- सेलेनियम टॉवर भी, प्लॉट नंबर 31 एउ 32, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकमगुड़ा, सेरेलिंगमपल्ली मंडल, हैदराबाद - 500032

ईमेल: einward.ris@kfintech.com **वेबसाइट:** www.kfintech.com, टोल फ्री नंबर 1800 309 4001

हम सभी शेयरधारकों से यह भी अनुरोध करते हैं कि वे संचार में सुगमता और लाभान्श के निर्बाध भूतान को सुनिश्चित करने के लिए डीपी (यदि शेयर डीमैट रूप में हैं) या आरटीडी (यदि शेयर भौतिक रूप में हैं) के साथ पैन, ईमेल आईडी, पता, मोबाइल नंबर और बैंक खाते के विवरण सहित केवाईसी विवरण अद्यान करें।

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाण-पत्र अपने डिजिटिजरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को प्रस्तुत कर उन्हें डीमैट रूप में परिवर्तित कर लें।

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

हस्ता/-
(अश्वीष मिश्रा)
कंपनी सचिव

PHOTO: SHUTTERSTOCK

GULVINE AULAKH
New Delhi, 27 October

The barb-laden social media trail kicked off by SpaceX founder Elon Musk's October 7 post that blamed "certain oligarchs" for blocking his Starlink satellites from entering India has set off a timely debate on how to develop India's already-frantic mobile telephone market even further.

Timely because Reliance Industries Ltd, whose chairman Mukesh Ambani was later named by Musk as the "oligarch" he had in mind, is headed for a ₹30,213 crore listing of its subsidiary Jio Platforms Ltd.

The posts by the world's first trillionaire entrepreneur signalled the need to flesh out two important ingredients of India's communication and inclusive growth ambitions — suitable technologies and competition.

The social media posts were sparked by a user who argued India urgently needed Starlink satellites because thousands of its villages were without 4G Wi-Fi networks.

According to Lauren Dreyer, who looks after Starlink business operations at SpaceX, the company is ready to serve India the moment it gets the green signal. Starlink had been ready for five years, having built up gateway sites with hundreds of antennae and controls in place to keep Indian user-data inside the country.

"We are ready to help Prime Minister Modi achieve his vision of 100 per cent connectivity throughout India — a vision all of our company, including Elon, shares," she told the India Mobile Congress.

The government in its defence denied allegations of bias, saying telecom licences had been granted to three mobile satellite services — Starlink, Bharti Enterprises-backed Eutelsat OneWeb and Reliance's Jio Satellite Communications. Security assessments were underway and, once granted, the firms could seek spectrum. Telecom minister Jyotiraditya Scindia added that Amazon LEO, formerly known as Project Kuiper, was also eyeing an India entry.

Sunil Mittal, chairman of Bharti Enterprises, the largest shareholder in the Eutelsat group, the merged entity of French satellite major Eutelsat and the UK's OneWeb, weighed in saying he, too, was waiting for approvals from the government.

Musk wouldn't back down: "There are many areas of India, as there are in all countries, with no Internet access, which denies children the opportunity for education and for small businesses the opportunity to sell their goods to a global market. Starlink would change their lives for the better."

"Ambani's profits will be lower, but he is not going out of business. And, obviously, if Starlink is too expensive in India, no one will buy it, so SpaceX will need to make pricing affordable," he said in yet another post.

That's the story of the

India and the battle for satellites

Sly innuendos aside, the recent social media exchanges involving Starlink make a case for harnessing satellites to roll out connectivity more evenly across India

tug-of-war which now appears to have quietened down.

Satcom, mobile or direct-to-device?
In its home market, SpaceX, meanwhile, announced an \$8-billion deal to buy a nationwide portfolio of 800 MHz spectrum from Grain Management, which included 14 megahertz of paired low-band airwaves, subject to approval from the US telecom regulator.

The impact on global telecom stocks was palpable. Telecom stocks fell across the US, Europe and Australia. In India, Bharti Airtel fell 1.44 per cent, Vodafone Idea 1.02 per cent and Reliance Industries 1.62 per cent.

Telecom sector expert Parag Kar said Starlink's existing satellite-to-phone service using a 6GHz spectrum works outdoors but struggles to penetrate walls. Adding the 800 MHz spectrum would solve that problem and make Starlink a real competitor to traditional telecom services providers. But analysts noted that without ground infrastructure or towers to propagate the 800 MHz network Starlink would not be able to offer its mobile service in any market.

"This purchase of frequency, which will take months to be confirmed by regulators, is for the US only. The underlying technology would, however, be applicable elsewhere, if SpaceX or a partner could obtain use of similar low-band frequency," said Simon Baker, senior research director at IDC, specialising in satellite and non-terrestrial connectivity.

In India, Reliance Jio owns a major chunk of the 800 MHz band. And for Starlink, setting up a tower network on its own will mean spending trillions of rupees. But the possibility of Starlink offering direct mobile services to consumers will be a concern to Indian players, especially after Musk said in an earnings call this month, "We will be building out our terrestrial networks so that there's broad-based connectivity anywhere in the world that SpaceX and Starlink are allowed to operate."

He added, "I think the demand for bandwidth is going to be dramatically higher than it is today. I think in three to five years there's probably a demand for 1,000x more bandwidth than there is currently, because AI or SI (super intelligence) agents will, on a per-agent basis, use far more bandwidth than a person, and there will be far more

agents than there are people. So this ends up requiring a several order of magnitude increase in communication bandwidth in order to satisfy that communication demand."

"The strategic significance of Starlink's spectrum moves is greater than the spectrum itself," said Akhilesh Tuteja, partner and national leader - clients and markets, and technology, media and telecommunications (TMT) at KPMG in India.

"It signals an ambition to move satellite connectivity closer to the mainstream mobile ecosystem, particularly through direct-to-device services. That could progressively blur the boundary between a satellite operator and a telecom operator," he said.

Satcom scalability
Interestingly, Jio Platforms Ltd, in its red herring prospectus, says satellite broadband was unlikely to scale in India because fixed

wireless access offers fibre-like speeds at cheaper rates. It put Starlink's entry plans at roughly ₹4,800 a month in the US and ₹2,500-4,500 in most African markets — much more than what the average consumer spends in India.

However, it also listed satellite competition as a key risk because satellite spectrum is allocated administratively rather than auctioned, which makes entry costs lower for satellite players than for ter-

Timeline of approvals given to Starlink

Date	Approval	Authority
May 2025	Letter of Intent (LoI)	Department of Telecommunications (DoT)
June 2025	Global mobile personal communications by satellite (GMPCS) Licence	DoT
July 2025	Satellite authorisation	IN-SPACe
2026	Security clearance (pending)	Law enforcement agencies under Ministry of Home Affairs

Pending security approvals

- Starlink, backed by SpaceX
- Jio Platforms & SES JV
- Eutelsat-OneWeb, backed by Bharti group

Upcoming satcom players

- Jio Platforms — own LEO constellation for India and global markets
- Amazon Leo — LEO constellation for global market and India

restrial operators. If satellites scale faster or are cheaper than expected, Jio conceded, its fibre and airframe offerings could become less competitive, and require additional investments. It argued that satellites were relevant for remote or hard-to-reach locations where terrestrial roll-out was challenging.

The pros and cons of satcom were listed out for investors since Jio is in the process of developing its own constellation of 1,600 satellites to provide connectivity, especially in remote areas. The company said it may even enter into strategic partnerships with leading global constellation providers.

"The Jio constellation will be coming late to the LEO (lower earth orbit) party. Starlink is already well-established globally and Amazon LEO is building up its satellite fleet. Other systems are being deployed or are planned, including from China. As a late entrant, Jio will face a competitive marketplace," IDC's Baker said.

"Satellite will become more integrated into mobile service in the future than it is now, and this justifies launching service at this

relatively early stage in development of direct phone-to-satellite technology," Baker said.

KMPG's Tuteja said that while the Indian satcom broadband market will initially be much smaller than the mobile market, the comparison can be misleading. "The attraction of satcom is not that it will replace mobile; it is that it can reach where mobile economics eventually runs out. A smaller market by connections does not necessarily mean a less strategic market," he said.

"In a country of India's geographic scale, even that edge of the network can represent a significant market."

Starlink's India dilemma
Starlink first tried to enter India in 2021 by taking pre-orders before it had a licence, and the government told it to stop. It received its satellite licence in June 2025, followed by the space regulator's approval and provisional trial spectrum. It is still to get security clearance, approval of foreign investment, and a final spectrum price.

However, the challenge isn't simply compliance: India wants satellite traffic from Indian users to be

monitorable and controllable within the country, with the ability to restrict services in "emergencies". Starlink's satellites relay data among themselves by laser, a design that enables it to offer its services anywhere in the world — services beamed from satellites are not constrained by political borders. This poses a security concern and makes compliance harder. Indian officials have also cited Starlink's role in conflict zones such as Ukraine and Iran to demand total control.

"Starlink is unwilling to comply with regulations requiring domestic infrastructure," a senior government official said.

To be sure, Starlink's two biggest Indian rivals are also its partners. Both Jio and Airtel signed deals with SpaceX in March 2025 to bring Starlink to their customers, subject to approvals.

RIL statement

On October 16, RIL broke its silence on Musk. A day after filing the RHP, the oil-to-telecoms conglomerate said it "welcomed competition in satellite communications", investment and innovation — homegrown or international. However, all operating in India must follow the rule of law, it said, adding its own satellite services await clearances.

Like Musk, Jio, too, cited the people of India.

"Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land," RIL said.

Musk's response was a brief "Much appreciated". But Starlink threw down the gauntlet anyway, saying it was "ready" — "ready to connect India with high-speed internet".

With Starlink planning terrestrial expansion and Jio gazing skywards, all that remains to be seen now is how this rivalry in the booming broadband industry serves India's unconnected.

Bank of Baroda
India's International Bank

<https://bankofbaroda.bank.in>

Request for Proposal (RFP) for Empanelment of Human Resource Recruitment Consultants for Hiring Manpower/ Capacity Building in Senior Management Positions as well as for Providing other support services in Bank of Baroda & its Wholly Owned Subsidiaries

Bank of Baroda has floated the following Request for Proposal (RFP) inter-alia inviting applications from eligible & suitable organisations for:

"Empanelment of Human Resource Recruitment Consultants for Hiring Manpower / Capacity Building for Senior Management Positions as well as for providing other support services in Bank of Baroda & its wholly owned subsidiaries."

The RFP Document containing complete details / Guidelines / Instructions is available through the "Tenders" section on the Bank's website <https://bankofbaroda.bank.in>

Any Addendum / Corrigendum / Clarification including modification in RFP Document shall be notified only through the Tenders Section of the Bank's website (<https://bankofbaroda.bank.in>). Applicants should refer the Bank's Website before submission of their proposal.

The last date of submission of the proposals is **17th November 2026, 5:00 pm.**

Place: Mumbai Date: 28.10.2026 Chief General Manager (HRM & Marketing)

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

अच्छे लोग, अच्छा बैंक Good people to bank with

Central Office, Investor Services, Union Bank Bhavan, 239 Vidhan Bhavan Marg, 12th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021 Phone: 022-22996536 Email: investorservices@unionbankofindia.bank.in Website: <https://unionbankofindia.bank.in>

IMPORTANT NOTICE TO SHAREHOLDERS SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGE OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Pursuant to SEBI Circular No. HO/38/13/11/2026-MISRD-POD/1/3750/2026 dated January 30, 2026, shareholders are hereby informed that a Special Window has been opened for a period of one (1) year, from February 5, 2026 to February 4, 2027, for the re-lodgement of transfer requests for physical share certificates.

This facility is applicable to transfer deeds lodged prior to April 1, 2019 which were rejected, returned, or not attended due to deficiencies in documents, process, or otherwise.

Shareholders who missed the earlier deadline may now avail this opportunity by submitting the requisite documents to the Bank's Registrar and Share Transfer Agent at the address mentioned below:

KFin Technologies Limited
Address: Unit: Union Bank of India, Selenium Tower B, Plot Nos. 31 & 32, Financial District Nanakramguda Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032 • Email: enward.ris@kfinetech.com • Website: www.kfinetech.com • Toll Free No 1800 309 4001

We also request all the shareholders to update KYC details including PAN, email id, address, mobile number and bank account details with the DP (if shares are held in demat form) or with RTA (if shares are held in physical form) to ensure the ease of communication and seamless payment of dividend.

Shareholders holding shares in physical form are requested to demat their shares by submitting share certificate to their Depository Participant (DP).

For Union Bank of India
SD/-
(ASHISH MISHRA)
Company Secretary

Place: Mumbai Date: 26.10.2026

MAZAGON DOCK SHIPBUILDERS LTD.
(Ship & Submarine Builders to the Nation)
A Government of India Enterprise, Ministry of Defence
CIN: L35100MH1934GO1002079
Registered and Corporate Office: Dockyard Road, Mumbai - 400010, Maharashtra, India
Ph: 022-23762015 E-mail: investor@mazdock.com <https://mazagondock.in>

UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2026

The Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for the quarter and half year ended September 30, 2026 are available on the Company's website at <https://mazagondock.in> and on the websites of BSE Limited & National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. In compliance with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the same can also be accessed by scanning the QR Code provided alongside.

Date: 27.10.2026 Place: Mumbai

For and on behalf of the Board of Directors
SD/-
Ruchir Agrawal
Director (Finance) & CFO
DIN - 10166533

UPDATE BANK DETAILS & CLAIM UNPAID/UNCLAIMED DIVIDENDS

Shareholders are requested to update their bank details with their Depository Participant (DP) at the earliest to ensure timely credit of dividends and to claim any unpaid/unclaimed dividends lying with the Company. Details of unpaid/unclaimed dividends are available on the Company's website at <https://mazagondock.in/English/pages/Dividend>. Shareholders are advised to take timely action to avoid transfer of eligible unpaid/unclaimed dividends and corresponding shares to the Investor Education and Protection Fund (IEPF), in accordance with applicable provisions. For assistance, shareholders may write to investor@mazdock.com or contact the Company's RTA, M/s Alankit Assignments Limited, 205-208 Anarkali Complex, Jhandewalan Extension, New Delhi - 110055; Website: www.alankit.com; Email: rta@alankit.com; Tel: +91 11 42541100 / 42541234; Fax: +91 11 23552001.

